

[2023] 2 एस. सी. आर. 247

ए.

गोवा का राज्य

बी.

समिट ऑनलाइन व्यापार समाधान (पी) लिमिटेड और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील संख्या 1700)

बी.

14 मार्च, 2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

भारत का संविधान: अनुच्छेद 226-उच्च न्यायालय का लिखित क्षेत्राधिकार-कार्रवाई का कारण/कार्रवाई के कारण का हिस्सा-यू/अनुच्छेद 226 (2) की अवधारणा-राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी पर 14 प्रतिशत कर लगाने के लिए गोवा राज्य द्वारा जारी अधिसूचना-जिसे गोवा सहित विभिन्न राज्यों में लॉटरी टिकट बेचने वाली कंपनी द्वारा सिक्किम उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में चुनौती दी गई है-गोवा राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी की श्रेणी से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन इस आधार पर कि राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के तहत अधिसूचना को किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर न्यायिक जांच के अधीन नहीं किया जा सकता है, इससे अधिक, कोई कारण नहीं है रिट अधिकारिता का आह्वान करने वाले पक्ष को यह खुलासा करना होगा कि कार्रवाई के कारण के समर्थन में अनुरोध किए गए अभिन्न तथ्य उच्च न्यायालय को विवाद का फैसला करने के लिए सशक्त बनाने का एक कारण बनते हैं और यह कि, कम से कम, उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ-ऐसे अनुरोध किए गए तथ्यों का चुनौती के विषय के साथ संबंध होना चाहिए जिसके आधार पर प्रार्थना की जा सकती है-वे तथ्य जो प्रासंगिक नहीं हैं या जो प्रार्थना को मंजूरी देने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, वे अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाले कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देंगे-ये मार्गदर्शक परीक्षण हैं-यह मानते हुए कि कार्रवाई के कारण का एक छोटा सा हिस्सा सिक्किम राज्य के भीतर उत्पन्न हुआ था, मंच संयोजकों की अवधारणा पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए था-कर उच्च न्यायालय द्वारा लगाया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

247 ए.

248 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

न्यायालय-उच्च न्यायालय ने आवेदनों को खारिज करने में गलती की-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया-कार्रवाई का कारण।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड बनाम हैरिबॉक्स स्वालराम

(2004) 9 एससीसी 786:[2004] 3 एस. सी. आर. 738; कुसुम इंगोत्स बनाम भारत संघ (2006) 4 एस. सी. सी. 254; अम्बिका इंडस्ट्रीज बनाम सी. सी. ई. (2007) 6 एस. सी. सी. 769:[2007] 7 एस. सी. आर. 685-संदर्भित।

बी.

कुक बनाम गिल (1873) 8 सी. पी. 107-संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

**[2004] 3 एससीआर 738**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

सी.

**(2006) 4 एस. सी. सी. 254**

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

**[2007] 7 एससीआर 685**

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील सं. 1700।

डी.

2018 के आई. ए. सं. 07,01 और 05 में सिक्किम उच्च न्यायालय के दिनांक 06.06.2018 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की सिविल अपील संख्या 1701 और 1702।

ई.

रवींद्र ए. लोखंडे, बबन जीत सिंह मेव, सुदर्शन मेनन, सत्यम सिंह, समरेंद्र बेउरा, राजेश राठौर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एन. वेंकटरमण, एएसजी, शिव मंगल शर्मा, सुश्री विशाखा, शशांक बाजपेयी, महालिंग पांडर्गे, सिद्धार्थ सिन्हा, राज बहादुर यादव, समीर अभ्यंकर, सुश्री निशी संगतानी, सुश्री वाणी वंदना छेत्री, सुश्री रूपल अग्रवाल, नरेंद्र कुमार, राघवेंद्र कुमार, आनंद कुमार दुबे, आशीष कुमार सिन्हा, निशांत वर्मा, श्रीमती अनीशा माथुर, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भारत बागला, सुश्री कीर्ति दधीच, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सुश्री अनीशा माथुर, आदित्य ए. पांडे, सुश्री रंजीता रोहतगी, अभिमन्यु।

एफ.

जी.

एच.

249

गोवा राज्य बनाम सारांश ऑनलाइन व्यापार समाधान (पी) लिमिटेड और ओआरएस।

हरियाणानी, संजीव कौशिक, श्रेयस अवस्थी, हिमांशु चक्रवर्ती, देवव्रत सिंह, सुश्री मुस्कान सुराना, अधिवक्ता।शरणार्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपांकर दत्ता, जे।

अनुमति दी गई

बी.

2. अपीलार्थी 2017 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 36, 2017 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 38 और 2017 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 59 में कई प्रत्यर्थीगणों में से एक है, जो सिक्किम उच्च न्यायालय (इसके बाद 'उच्च न्यायालय', संक्षेप में) की फाइल पर लंबित है। उक्त तीन रिट

याचिकाओं में अलग-अलग आवेदन अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए थे, जिसमें प्रत्यर्थागणों की श्रेणी से इसे हटाने की मांग की गई थी। अपीलार्थी ने उक्त आवेदनों में अनुरोध किया था कि, अन्य बातों के साथ-साथ, उसके द्वारा जारी एक अधिसूचना को रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी और यदि इस तरह की अधिसूचना को चुनौती का विषय बनाया जा सकता है, तो गोवा में बॉम्बे का उच्च न्यायालय उपयुक्त न्यायालय है जहां उपचार किया जाना चाहिए। अपीलार्थी के अनुसार, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के तहत जारी अधिसूचना को किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक जांच के अधीन नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब उस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कोई कारण सामने नहीं आया हो। यह आगे अनुरोध किया गया कि चूंकि रिट अधिकार क्षेत्र के आह्वान के लिए कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए रिट याचिकाओं को अपीलार्थी के खिलाफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया गया एक अन्य तथ्य यह था कि इसी अधिसूचना को गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष सेरेनिटी ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या <आई. डी. 1 में चुनौती दी गई थी और प्रवेश के बाद ऐसी रिट याचिका अंतिम सुनवाई के लिए लंबित थी। अपीलार्थी द्वारा यह आग्रह किया गया था कि विचारों के टकराव से बचने के लिए, रिट याचिकाकर्ता या तो स्वतंत्र रूप से गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अधिसूचना को चुनौती दे सकते हैं या डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या में हस्तक्षेप के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

3. उच्च न्यायालय ने 6 जून, 2018 के एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा तीनों आवेदनों को खारिज कर दिया है। ये तीन अपीलें, विशेष अनुमति द्वारा, ऐसे निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं।

जी.

4. चूंकि एक सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती दी जा रही है, इसलिए हम इन अपीलों पर इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं। 5. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद 'सी. जी. एस. टी. अधिनियम', संक्षेप में) के तहत जारी विभिन्न अधिसूचनाएं और

एच.

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

ए.

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद संक्षेप में 'आई. जी. एस. टी. अधिनियम') को गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और सिक्किम राज्यों द्वारा जारी दर-अधिसूचनाओं के साथ-साथ तीनों रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है। अन्य बातों के साथ-साथ, चुनौती गोवा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए गोवा सरकार द्वारा 30 जून, 2017 को जारी "No.01 2017" वाली एक अधिसूचना के लिए है।

बी.

"राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत (एल) ऊदबिलाव" पर 14 प्रतिशत की दर से कराद.

रिट याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के उच्च विशेषाधिकार रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए यह घोषणा करने की मांग की है कि विवादित अधिसूचना असंवैधानिक और अवैध है।

सी.

6. इन अपीलों पर निर्णय के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष को वापस करने में उचित था कि

कार्रवाई के कारण का कम से कम एक हिस्सा अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है

इस न्यायालय के "और इस तरह के निष्कर्ष पर आधारित, आवेदनों को खारिज करने के लिए। 7. अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिकाओं को प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने के बाद इस न्यायालय द्वारा 12 नवंबर, 2018 को नोटिस जारी किया गया था।

डी.

8. नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई भी रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश नहीं हुआ है। हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता और भारत संघ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ-साथ अन्य उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना है।

ई.

9. इन अपीलों पर निर्णय के उद्देश्य से, 2017 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 38 में याचिका के कथनों पर ध्यान दिया जा सकता है। ए प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी, "सिक्किम राज्य के भीतर और साथ ही राज्य के बाहर सिक्किम सरकार द्वारा संचालित और आयोजित लॉटरी टिकटों की खरीद और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है",

एफ.

रिट याचिकाकर्ता।याचिका दायर करने वाली कंपनी सिक्किम, पंजाब, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों में लॉटरी टिकट बेचती है।यह अनुरोधित मामला है कि लॉटरी टिकट, जो याचिका दायर करने वाली कंपनी द्वारा प्रदान किए जाते हैं, हैं

“जो लॉटरी सिक्किम राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, यह राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी नहीं है, जिसके लिए 28 प्रतिशत की उच्च कर दर के तहत जी. एस. टी. का निर्वहन करने की आवश्यकता है।यह मामला

जी.

स्थापित करने की मांग यह है कि यदि "(एल) ऊदबिलाव के बीच का अंतर

"और" (एल) राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत ऊदबिलाव "

जैसा कि विवादित अधिसूचना द्वारा किया गया है, वही प्रत्यक्ष रूप से अवैध होगा और इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी।

एच.

251

गोवा राज्य बनाम सारांश ऑनलाइन व्यापार समाधान (पी) लिमिटेड और ओआरएस।  
[दीपांकर दत्त, जे।] ए.

ए.

10. 2017 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 38 में प्रार्थनाओं का निम्नलिखित प्रभाव है:

“(i) सिक्किम, गोवा, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों की विवादित अधिसूचनाओं 01/2017 केंद्रीय कर (दर), 01/2017 एकीकृत कर (दर), 01/2017 और राज्य दर अधिसूचनाओं को इस हद तक अलग रखें कि यह 'राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी' के बीच एक भ्रामक उप-वर्गीकरण बनाकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी), 301, 304 और सी. जी. एस. टी., एस. जी. एस. टी. और आई. जी. एस. टी. अधिनियम के भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी के रूप में लॉटरी टिकटों की आपूर्ति पर कर की अलग-अलग दरों को लागू करता है और आगे यह मानता है कि सभी राज्य संचालित लॉटरी के मामलों में केवल 12 प्रतिशत विज्ञापन मूल्य कर समान रूप से लगाया जा सकता है।

बी.

सी.

((ii) ब्याज के साथ केवल 12 प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान करने के लिए याचिकाकर्ता के दायित्व के मुकाबले 28 प्रतिशत की दर से भुगतान किए गए अंतर शुल्क का प्रत्यक्ष धनवापसी।

डी.

(iii) सिक्किम, गोवा, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों की विवादित अधिसूचनाओं 01/2017 केंद्रीय कर (दर), 01/2017 एकीकृत कर (दर) 01/2017 और राज्य दर अधिसूचनाओं को इस हद तक अलग रखें कि यह पुरस्कार राशि को कम किए बिना लॉटरी टिकट के अंकित मूल्य पर कर लगाता है, लॉटरी टिकट का घटक जब उक्त राशि कभी भी याचिकाकर्ता लॉटरी व्यापार की आय का हिस्सा नहीं बनती है।”

ई.

11. उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश देते हुए कहा कि रिट याचिकाकर्ता न केवल जी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत अपीलार्थी द्वारा जारी विवादित अधिसूचना से बल्कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम के साथ-साथ आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत विवादित अधिसूचना जारी करने में केंद्र सरकार के अधिनियम से भी व्यथित थे, जिसमें सिक्किम राज्य द्वारा आयोजित, प्रचारित और संचालित लॉटरियों पर कर (जी. एस. टी.) लगाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह जी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत जी. एस. टी. की वास्तविक घटना नहीं है जो रिट याचिकाओं में आक्षेपित है, बल्कि संसद के साथ-साथ गोवा राज्य सहित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधान हैं जिनके द्वारा उन्होंने लॉटरियों पर जी. एस. टी. लगाने की मांग की थी। रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय का यह विचार था कि, कम से कम, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र के साथ उत्पन्न हुआ था। उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि चूंकि डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या पर नोटिस जारी किया गया था।

एफ.

जी.

एच.

252

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

36 और 2017 का 38,17 जुलाई, 2017 को, 28 सितंबर, 2017 को गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या में नियम जारी किए जाने से बहुत पहले, अपीलार्थी द्वारा हटाने के लिए कोई आधार स्थापित नहीं किया गया था। इसलिए, हटाने की मांग करने वाले अंतरिम आवेदन खारिज कर दिए गए। 12. रिट याचिका पर विचार करने और मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के समर्थन में, याचिका दायर करने वाली कंपनी ने यह कहा है:

बी.

“29. कि उनके माननीय न्यायालय को उक्त रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि कार्रवाई का कारण केवल सिक्किम में ही उत्पन्न होता है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थीगण दोनों इस माननीय उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं।”

सी.

इन दो सजाओं के अलावा, उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के समर्थन में और कुछ नहीं कहा गया है।

13. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि याचिका दायर करने वाली कंपनी के अनुसार कार्रवाई का कारण केवल सिक्किम में उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कि कार्रवाई का पूरा कारण और इसका हिस्सा नहीं है; इसके अलावा, यह कहा गया है कि सभी प्रत्यर्थीगण उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।

डी.

14. एक रिट याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के रूप में एक आपत्ति पर विचार करते समय इस आधार पर कि कार्रवाई का कारण उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न नहीं हुआ है, एक उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से याचिका ज्ञापन में किए गए कथनों के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा जिसमें सामग्री को सही और सही माना गया है। यही मूल सिद्धांत है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने 2017 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 38 के याचिका ज्ञापन पर गौर किया है और यह पता लगाने के लिए व्यर्थ खोज की है कि याचिका दायर करने वाली कंपनी द्वारा कार्रवाई के कारण का कम से कम हिस्सा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कैसे उत्पन्न हुआ है।

ई.

एफ.

15. यह एक ऐसा मामला है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के खंड (2) को रिट याचिकाओं पर विचार करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र के साथ लागू किया गया है। खंड (2) का संवैधानिक अधिदेश यह है कि उसमें निर्दिष्ट 'कार्रवाई का कारण' कम से कम उन क्षेत्रों के भीतर आंशिक रूप से उत्पन्न होना चाहिए जिनके संबंध में उच्च

न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है जब खंड (1) द्वारा प्रदत्त रिट शक्तियों का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया जाता है, इसके बावजूद कि सरकार या प्राधिकरण या व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर नहीं है। संविधान में 'कार्रवाई का कारण' अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, कुक बनाम में लॉर्ड ब्रेट द्वारा दी गई 'कार्रवाई के कारण' की क्लासिक परिभाषा।

जी.

एच.

253

गोवा राज्य बनाम सारांश ऑनलाइन व्यापार समाधान (पी) लिमिटेड और ओआरएस।  
[दीपांकर दत्त, जे।] ए.

ए.

गिल **1** ने कहा कि "कार्रवाई के कारण का अर्थ है हर वह तथ्य जिसे वादी के लिए अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए, यदि पार किया जाता है, तो साबित करना आवश्यक होगा", इसके द्वारा स्वीकार किया गया है।

कुछ फैसलों में अदालत। यह स्वयंसिद्ध है कि बिना किसी कारण के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि, एक रिट याचिका के संदर्भ में, इस तरह की 'कार्रवाई का कारण' क्या होगा, वह भौतिक तथ्य हैं जो रिट याचिकाकर्ता के लिए अनुरोध करने और राहत प्राप्त करने के लिए साबित करने के लिए अनिवार्य हैं जैसा कि दावा किया गया है। इस प्रश्न का निर्धारण कि क्या अनुरोध किए गए तथ्य कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं, अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक अभ्यास शामिल होगा कि तथ्य, जैसा कि अनुरोध किया गया है, कार्रवाई के कारण का एक भौतिक, आवश्यक या अभिन्न हिस्सा है। इस प्रकार निर्धारित करने में, यह पदार्थ का सार है जो प्रासंगिक है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष को यह खुलासा करना होगा कि कार्रवाई के कारण के समर्थन में अनुरोध किए गए अभिन्न तथ्य उच्च न्यायालय को विवाद का फैसला करने के लिए सशक्त बनाते हैं और कम से कम, उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। इस तरह के तर्कित तथ्यों का चुनौती के विषय के साथ संबंध होना चाहिए जिसके आधार पर प्रार्थना की जा सकती है। वे तथ्य जो प्रार्थना के अनुदान के लिए प्रासंगिक या उपयुक्त नहीं हैं, वे अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाली कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देंगे। ये मार्गदर्शक परीक्षण हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

16. यहाँ, गोवा सरकार द्वारा उस व्यवसाय के संबंध में कर लगाया गया है जिसे याचिका दायर करने वाली कंपनी गोवा के क्षेत्र के भीतर चला रही है। इस तरह का कर याचिका दायर करने वाली कंपनी द्वारा देय है जो सिक्किम के क्षेत्र में कोई व्यवसाय करने के संबंध में नहीं है। इसलिए, केवल इसलिए कि याचिका दायर करने वाली कंपनी का कार्यालय गंगटोक, सिक्किम में है, यह अपने आप में याचिका दायर करने वाली कंपनी को उच्च न्यायालय में जाने के लिए अधिकृत करने वाली कार्रवाई का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है। हम राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए ऐसा मानते हैं। हैरिबॉक्स स्वालराम 2. विवादित अधिसूचना से उत्पन्न होने वाला तत्काल नागरिक या बुरा परिणाम यह है कि याचिका दायर करने वाली कंपनी को गोवा सरकार को 14 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना पड़ता है। देयता गोवा के क्षेत्र के भीतर याचिका दायर करने वाली कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय की विशिष्ट प्रकृति के लिए उत्पन्न होती है। दलीलें यह नहीं दर्शाती हैं कि विवादित अधिसूचना का कोई प्रतिकूल परिणाम उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में महसूस किया गया है। इस समय हम नहीं हैं

एफ.

जी.

1 (1873) 8 सीपी 107 2 (2004) 9 एससीसी 786

एच.

254

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

विवादित अधिसूचना की अनुसूची II [@6 प्रतिशत] और अनुसूची IV [@14 प्रतिशत] में परिकल्पित अंतर शुल्क से संबंधित। यह एक ऐसा मामला है जिसका मुकदमे के गुण-दोष पर असर पड़ता है। मामला लंबा और छोटा है कि याचिका दायर करने वाली कंपनी को विवादित अधिसूचना की अनुसूची IV के तहत गोवा राज्य में लॉटरी टिकट बेचने के लिए गोवा सरकार द्वारा लगाए गए 14 प्रतिशत कर का भुगतान करने का दायित्व वहन करना पड़ता है। यह याचिका ज्ञापन से इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि कैसे गोवा राज्य में व्यवसाय करने के लिए कर लगाने वाली विवादित अधिसूचना याचिका दायर करने वाली कंपनी को उच्च न्यायालय द्वारा विचार की जाने वाली रिट याचिका के लिए सिक्किम के क्षेत्र के भीतर कानूनी गलती का विषय बनाती है।

बी.

17. हमारी राय में, उच्च न्यायालय को याचिका ज्ञापन पर विचार किए बिना अपीलार्थी के आवेदनों को खारिज नहीं करना चाहिए था, जिसमें इस बात की कोई झलक नहीं है कि उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर कार्रवाई का कारण कैसे उत्पन्न हुआ या बिना किसी अभिवचन के कि सिक्किम के क्षेत्र के भीतर कोई अधिकार कैसे प्रभावित हुआ है।

सी.

डी.

18. अन्यथा भी, उच्च न्यायालय अंतरिम आवेदनों को खारिज करने में उचित नहीं था। यह मानते हुए कि कार्रवाई के कारण का एक छोटा सा हिस्सा सिक्किम राज्य के भीतर उत्पन्न हुआ था, मंच संयोजकों की अवधारणा पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए था। जैसा कि आयोजित किया गया है

कुसुम इंगोट्स बनाम भारत संघ **3** और अम्बिका मामले में इस न्यायालय द्वारा

उद्योग बनाम सी. सी. ई. 4, भले ही कार्रवाई के कारण का एक छोटा सा हिस्सा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, लेकिन यह अपने आप में एक निर्धारक कारक नहीं हो सकता है जो उच्च न्यायालय को अपीलार्थी के खिलाफ रिट याचिकाओं को योग्यता के आधार पर, विवादित अधिसूचना के मामले का निर्णय लेने के लिए जीवित रखने के लिए मजबूर करता है।

ई.

19. उपरोक्त कारणों से, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदनों को खारिज करने में गलती की है। नतीजतन, 6 जून, 2018 के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है। दीवानी अपीलों को बिना किसी लागत के अनुमति दी जाती है।

एफ.

20. अपीलार्थी को 2017 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 36,38 और 59 में प्रत्यर्थागणों की श्रेणी से हटा दिया जाएगा।

जी.

21. उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश इस परिणाम के साथ खाली हो जाता है कि उच्च न्यायालय कानून के अनुसार अन्य प्रत्यर्थागण के खिलाफ रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है।

एच.

255

गोवा राज्य बनाम सारांश ऑनलाइन व्यापार समाधान (पी) लिमिटेड और ओआरएस।  
[दीपांकर दत्त, जे।]

22. हालाँकि, यह आदेश संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार 30 जून, 2017 की अधिसूचना पर हमला करने के लिए उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाने से नहीं रोकेगा, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: शाश्वत जैन, एलसीआरए)

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.